(iii) NEED FOR TAKING STEPS TO HELP MANUFACTURERS OF ACETIC ACID

DR. KRUPASINDHU BHOI (Sambalpur): Sir, the alcohol-based chemical industry is facing a crisis of over-supply but the worst hit in the line is the manufacturers of acetic acid who find it difficult to market their products.

The root cause of the problem is that the installed capacity in the country is far in excess of the domestic demand and the problem stands aggravated because of the government permission to effect the import from abroad.

The consumption of the acid is well below the supply right now and this has induced manufacturers to offer substantial price concession to boost their individual sales. In the past few months, the prices are slashed down by Rs. 2,000 a tonne to Rs. 3,000 a tonne and yet this has not pushed up the total sales of the acid industry as a whole by any significant margin.

Unless some sort of help is extended by the Government, as many as 14 manufacturers of acetic acid in the country, the individual capacity of most of whom ranging between 1,500 tonnes and 900 tonnes will continue to suffer. The overseas sales would relieve the domestic glut to some extent and encourage the manufacturers to maintain the high level of their production.

In view of this, I suggest that the Government of India should initiate efforts to promote exports of this particular chemical. All sorts of help should also be extended to market their product in the domestic market.

(iv) GRANT OF PENSION TO FAMILY MEMBERS OF FREEDOM FIGHTERS WHO SUFFERED IMPRISONMENT IN 1930.

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को या उनके स्वर्गवास के बाद उनके पत्नी या बच्चों को पेंशन दी जाती है लेकिन देश में ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हैं जिन्हें 1930 में जेल की सजा 6 माह या इसके ऊपर की सजा दी गई थी। बाद में गांधी-इर्विन पैक्ट, 1930 के तहत उन स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों का 6 मास से पहले ही छोड़ दिया गया है। इन स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को या उनके पत्नी या बच्चों को कोई पेंशन नहीं मिल रही है। आज उन स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों में से बहुत सारे या तो स्वर्गवास हो चुका है लेकिन उनके पीछे पत्नी या बच्चों की हालत बहुत खराब है। खाने पीने या रहने का कोई ठिकाना नहीं है और दूसरों पर आश्रित हो कर जीवन यापन बड़ी कठिनाई से कर रहे हैं। उदाहरणतः मेरे क्षेत्र से भंडारा (महाराष्ट्र) की रहने वाली एक महिला हैं। गांधी इर्विन पैक्ट के तहत उन के पति को साढ़े चार माह में ही जेल से छोड़ दिया गया जब कि उन्हें 6 माह की सजा हुई थी। उनका स्वर्गवास हुये दो वर्ष हो चुके हैं। उनको पेंशन मिलती थी लेकिन उनकी पत्नी को पेंशन नहीं मिल रही है। मैंने इसके लिये प्रयत्न भी किये, बताया जाता है कि सजा 6 माह से कम भोगी है इस बजह से पेंशन नहीं मिल सकती। फिर उनको पेशन क्यों दी गई जब कि आज उनकी पत्नी का जीवन, यापन, पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हैं। जिन्हें गांधी इर्विन पैक्ट के अन्तर्गत 6 माह की सजा होने के बाद भी पहले छोड़ दिया गया। ऐसे सभी स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को पेंशन दिया जाय जिससे उनके पत्नी या बच्चों को जीवन-यापन करने में जो तफलीफ हो रही है वह तफलीफ दूर हो सके।

(v) ACUTE SHORTAGE OF ELECTRICITY IN MATHURA DISTRICT OF UTTAR PRADESH.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : मान्यवर, देश में बिजली की कमी है। सबसे अधिक

[श्री दिगम्बर सिंह]

कमी उत्तर प्रदेश और मथुरा जिले में है । इसका एकमात्र हल यह है कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था स्वयं करे । यदि शीघ्र बिजली की समस्या हल नहीं की जाती तो उससे रबी की फसल के उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा । जितने समय देने की घोषणा की जाती है उसकी चौथाई समय भी नहीं मिलता । तेल शोधक कारखाने, मथुरा में जितना बिजली उत्पादन की क्षमता है उतनी कारखाने को आवश्यकता नहीं । कारखाने के अतिरिक्त बिजली को माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले और नगर को दे दें। तो उससे सिंचाई को बिजली अधिक मिल जायेगी और मथुरा नगर जो अव्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश का सबसे गन्दा नगर है, और रात के अंधेरे में जनता और देश और विदेश से आये यात्री गन्दगी से परेशान होते हैं और बिजली के बिना नल न चलने से प्यासे मरते हैं उनको भी सुविधा होगी ।

माननीय ऊर्जा मंत्री दिवाली पर कारखाने की बची हुई बिजली लेकर कृष्ण भगवान की जन्म स्थली और बृजवासियों को कम से कम दिवाली पर अंधेरे से बचाने की कृपा करें और बड़ी कृपा हो यदि पवित्र नगरी की गन्दगी और अंधेरे को भी आ कर देख लें ।

(vi) NEED FOR REMOVAL OF ANOMALY BETWEEN B.A. (MATHS) AND B.Sc. (MATHS.) IN REGARD TO APPOINTMENTS IN KENDRIYA VIDYALAYAS.

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): Sir, in the Directorate of Education, Delhi, for appointment to the Grade o. T.G.T. in the group of Science A, only B.Sc. (with Chemistry, Physics and Mathematics) are eligible whereas the candidates with the qualification of B.A. (maths) are not considered eligible. While on the one hand, there is an acute shortage of mathematics teachers in the Directorate of Education, on the other, B.A. (Maths) candidates are rotting both in the Employment Exchange and M.C. Primary Schools, Delhi, for the last several years. Moreover, B.Sc. candidates are hardly available at present to meet the full demand of the Directorate of Education.

It is quite strange that in the Kindriya Vidyalayas, in all the aided schools in Delhi and also in all the Government Schools in various States like Punjab, Haryana, U.P. and Himachal Pradesh, B.A. (Maths) candidates are invariably considered eligible for the post of T.G.T. (Maths). Keeping in view the shortage of mathematics teachers in the Directorate of Education, I urge upon the Minister of Education and Culture to look into the matter and remove this anomaly by making all such B.A. (Maths) candidates eligible for appointment as mathematics teachers in the Directorate of Education. By doing so a great number of candidates registered in the Employment Exchange, Delhi as well as Assistant teachers in M. C. Primary Schools, Delhi would be benefited.

(vii) NEED TO STOP IMPORT OF SYNTHETIC YARN AND TO PROMOTE EXPORT OF COTTON

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में सिन्थेटिक यार्न बाहर के देशों से बड़ी भारी तादाद में आ रहा है और कपड़ा मिलों वाले आज जो कपड़ा बना रहे हैं, उसमें 80 प्रतिशत सिन्थेटिक यार्न और 20 प्रतिशत कोटन यार्न इस्तेमाल कर रहे हैं ।

हमारे देश में जो कोटन पैदा हो रही है, वह भी बड़ी भारी तादाद में हो रही है और इस देशी कोटन और नरमे को खपत का स्थान सिन्थेटिक यार्न ने ले लिया है और एक्सपोर्ट हमारी कोटन का नहीं के बराबर हो रहा है । इस सबका नतीजा यह हो रहा है कि कोटन का भाव दिन पर दिन गिरता जा रहा है ।

कोटन के उत्पादन में जो खर्चा इस मंहगाई के जमाने में हो रहा है, उसका उचित मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है,